उत्तरांचल शासन राज्य पुनर्गठन विभाग संख्याः 309/रा०पु० / वि०का०अ० / 4 / 2003. देहरादून, दिनांक 09 अक्टूबर, 2003

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन

आप अवगत है कि उ०प्र० राज्य पुनर्गठन अधिनियम-2000 के अर्न्तगत उ०प्र० एवं उत्तरांचल के मध्य कार्मिकों के विभाजन की कार्यवाही हेतु राज्य परामशीय समिति गठित है जिसकी संस्तुति/अनुशंसा/परामर्श पर भारत रारकार द्वारा अन्तिम आवंटन की कार्यवाही की जानी है । जिसके अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन अपने सामान्य आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2001 के माध्यम से कर दिया गया है ।

राज्य पुनर्गठन विभाग के संज्ञान में आया है कि पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तिम रूप से उत्तरांचल आवंटित कार्मिकों को हार्डशिप केसेज के अन्तेगत उ०प्र० के लिए कार्यमुक्त किये जाने हेतु राज्य परामर्शीय समिति को संदर्ग मेंजे जा रहे है एवं कुछ प्रकरणों में सदस्य सचित राज्य परामर्शीय समिति को भेजे गये संदर्भ के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की भेजे गये संदर्भ के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की सहमिति मानते हुए उ०प्र० हेतु अवमुक्त किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि वृंकि पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है अतः इन संवर्गों के कार्मिकों के प्रकरणों को राज्य पूरामर्शीय समिति को संदर्भित किये जाने का औचित्य नहीं है । ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के उत्तर प्रदेश के लिए रोवा स्थानान्तरण (Transfer of Services) के लिए राक्षम स्तर पर उच्चादेश प्राप्त करके उ०प्र० शासन को सहमति हेतु संदर्भित करेंगे एवं उ०प्र० शासन की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे ।

कृपया पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्गिकों के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

> (नृप सिंह नपलच्याल) प्रमुख सचिव